

संख्या 04/XXX(2)/2013

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

श्री- प्रसाद / नरकान.
कृपया समस्त कोषाधिकारी
को पत्र-वितरण के
रूप में
9.1.13

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: 08 जनवरी, 2013

विषय - अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों द्वारा हड़ताल/कार्य बहिष्कार के संबंध में।

महोदय,

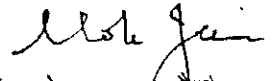
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायः कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में हड़ताल/कार्य बहिष्कार किए जाते हैं, जिससे जहां एक ओर जन सामान्य को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है वहीं शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। इस संबंध में सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

- (1) "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के अनुरूप हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाए। प्रत्येक माह की 24 तारीख तक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारी का विवरण आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराया जाएगा तथा कोषागार द्वारा तदनुसार हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कर्मचारी का हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाए।
- (2) प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाए और यदि कोई कर्मचारी उपस्थिति पंजीका में हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें भी हड़ताल/कार्य बहिष्कार में सम्मिलित माना जाए एवं उनके सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

- (3) हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि को बाद में किसी भी दशा में उपाजित अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश के रूप में अगणित नहीं किया जाएगा बल्कि इस अवधि को संबंधित कर्मचारी द्वारा सेवा में व्यवधान माना जाएगा।
- (4) हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत न किया जाए।
- (5) जिन सेवाओं में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हैं, वहां उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।
- (6) हड़ताल/कार्य बहिष्कार की अवधि में जो कर्मचारी कार्य पर आते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
- (7) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

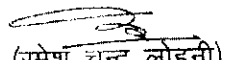

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव।

संख्या 04 (1)/XXX(2)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक सूचना, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी निदेशक, एन0आइ0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।


निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,

23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2512/21(32)/प्रावि0 विविध-2/नि0को0वि0से0/2013, दिनांक 10 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि, समस्त, कोषागार/उपकोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड/वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, भु0 एवं ले0का0नई दिल्ली को उक्त शासनादेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(रमेश चन्द्र सेमवाल)
अपर निदेशक।